

आयुर्वेदिक चिकित्सक

3060. श्री नारायण तातू राणे:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में आयुर्वेदिक चिकित्सकों हेतु कितने पद स्वीकृत हैं;
- (ख) देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सकों की संख्या का श्रेणीवार और राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) सम्पूर्ण देश में सभी श्रेणियों में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के रिक्त पदों की कुल संख्या का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
- (घ) इन रिक्त पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
- (ङ) विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्षवार और राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार कुल कितने आयुर्वेद चिकित्सक उत्तीर्ण हुए हैं;
- (च) क्या सरकार का ऐसी नियुक्तियों के लिए राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रत्येक राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और
- (छ) क्या सरकार का आयुर्वेद में एकीकृत पाठ्यक्रम को पुनः आरंभ करने का भी कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (च): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, सभी श्रेणियों में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पदों को स्वीकृत करने और भरने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती है और तदनुसार, केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के 121 स्वीकृत पदों में से एक पद वर्तमान पदधारक की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त है। आयुष मंत्रालय ने रिक्त पद को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन की नीति अपनाई है, जिससे रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के लिए विकल्प चुनने में मदद मिलती है। आयुष चिकित्सकों/पैराचिकित्सकों की संविदात्मक नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सहयोग दिया जा रहा है, जबकि आयुष अवसंरचना, उपकरण/फर्नीचर और औषधियों के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा साझा जिम्मेदारियों के रूप में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। पीएचसी में सह-स्थापित आयुष सुविधाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति संलग्नक-I पर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, राज्य बोर्ड/परिषद/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक-II** पर दी गई है।

(छ) : आयुर्वेद में एकीकृत पाठ्यक्रम को पुनः आरंभ करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों नामतः आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा (एएसयूएस) पर उचित अभिविन्यास और मॉड्यूल के अनुसार विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए एमबीबीएस, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी के लिए आयुष मॉड्यूल तैयार किया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सह-स्थापित आयुष सुविधाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पीएचसी
1	आंध्र प्रदेश	273
2	अरुणाचल प्रदेश	50
3	असम	71
4	बिहार	0
5	छत्तीसगढ़	454
6	गोवा	22
7	गुजरात	868
8	हरियाणा	106
9	हिमाचल प्रदेश	0
10	झारखंड	97
11	कर्नाटक	375
21	केरल	0
13	मध्य प्रदेश	283
14	महाराष्ट्र	20
15	मणिपुर	78
16	मेघालय	54
17	मिजोरम	10
18	नागालैंड	9
19	ओडिशा	886
20	पंजाब	94
21	राजस्थान	146
22	सिक्किम	4
23	तमिलनाडु	475
24	तेलंगाना	352
25	त्रिपुरा	84
26	उत्तराखंड	44
27	उत्तर प्रदेश	627
28	पश्चिमी बंगाल	368
29	अंडमान और निकोबार द्वीप	20
30	चंडीगढ़	28
31	दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव	9
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0
33	जम्मू-कश्मीर	372
34	लद्दाख	32
35	लक्षद्वीप	4
36	पुडुचेरी	39
कुल		6354

स्रोत: दिनांक 30.06.2024 तक एनएचएम-एमआईएस डेटाबेस के अनुसार

पिछले पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सकों की राज्य/संघ राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक
1	आंध्र प्रदेश	569
2	अरुणाचल प्रदेश	37
3	असम	221
4	बिहार	652
5	छत्तीसगढ़	1097
6	दिल्ली	337
7	गोवा	156
8	गुजरात	4036
9	हरियाणा	2073
10	हिमाचल प्रदेश	1296
11	जम्मू	274
12	झारखंड	13
13	कर्नाटक	9741
14	केरल	587
15	मध्य प्रदेश	1508
16	महाराष्ट्र	13769
17	ओडिशा	3
18	पंजाब	1517
19	राजस्थान	1773
20	तमिलनाडु	446
21	उत्तर प्रदेश	3703
22	उत्तराखंड	761
23	पश्चिमी बंगाल	372
कुल		44941